	के राज्य पारेषण यूटीलिटी (एसटीयू) के प्रमुख #	
5	दक्षिणी क्षेत्रीय विद्युत समिति के सदस्य सचिव	सदस्य
6	एनटीपीसी, एनएचपीसी और एसईसीआई के सीएमडी/एमडी/अध्यक्ष	सदस्य
7	मुख्य अभियंता (विद्युत प्रणाली स्कंध से), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण *	सदस्य सचिव

 # एसटीयू अपनी संबंधित वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।

** केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मनोनीत किया जाना है।*

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति (पारेषण योजना) (एनईआरपीसीटीपी):

1	सदस्य (विद्युत प्रणाली), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)	अध्यक्ष
2	मुख्य प्रचालन अधिकारी, केंद्रीय पारेषण यूटीलिटी (पावरग्रिड)	सदस्य
3	निदेशक (सिस्टम ऑपरेशन), पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सदस्य
4	असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के राज्य पारेषण यूटीलिटियों (एसटीयू) के प्रमुख #	सदस्य
5	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति के सदस्य सचिव	सदस्य
6	एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसईसीआई और नीपको के सीएमडी/एमडी/अध्यक्ष	सदस्य
7	मुख्य अभियंता (विद्युत प्रणाली स्कंध से), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण *	सदस्य सचिव

 # एसटीयू अपनी संबंधित वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।

** केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मनोनीत किया जाना है।*

2. आरपीसीटीपी के संदर्भ शर्तें (टीओआर) इस प्रकार हैं:

(i) क्षेत्र में पारेषण प्रणाली की तिमाही समीक्षा करना ; उत्पादन क्षमता में वृद्धि और क्षेत्र के विभिन्न भागों में मांग का आकलन करना; और अंतर-क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रस्ताव तैयार करना। पारेषण आयोजना को उन क्षेत्रों को ध्यान में रखना आवश्यक होगा जहां उत्पादन बढ़ने की संभावना है और उन क्षेत्रों में जहां लोड की मांग बढ़ेगी ताकि किसी भी समय में पारेषण प्रणाली देश के हर कोने में मांग को पूरा कर पाएगी और ग्रिड के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन से पहले पारेषण प्रणाली विकसित करने की टैरिफ नीति के तहत अधिदेश का पालन करने के लिए सक्षम हो पाएगी।

(ii) निकट, मध्यम और दीर्घावधि में पारेषण प्रणाली की आवश्यकताओं का आकलन करना और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारेषण योजनाएँ तैयार करना। ऐसा करते समय अगले 15-20 वर्षों के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना को भी ध्यान में रखा जा सकता है और तदनुसार योजना प्रक्रिया के दौरान प्रणाली में अपेक्षित भत्ता/मार्जिन को शामिल किया जा सकता है।

(iii) कनेक्टिविटी और एक्सेस के लिए आवेदनों की जांच करना और सुनिश्चित करना कि इन्हें शीघ्रता से प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि अपेक्षित शुल्क/प्रभार का भुगतान किया गया हो।

(iv) पारेषण योजनाओं से जुड़े अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम नेटवर्क की समीक्षा करना।

(v) अंतरा-राज्यीय पारेषण प्रस्तावों की जांच और मूल्यांकन करना।

(vi) अंतर-क्षेत्रीय ग्रिड सुदृढ़ीकरण योजनाओं के निर्माण की समीक्षा और सुविधा प्रदान करना ।

3. आरपीसीटीपी यह सुनिश्चित करने के उपाय करेंगे कि पारेषण क्षमता बाजार की मांग के अनुसार क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों और क्षेत्र के बाहर विद्युत को भेजने में सक्षम है। वे त्रैमासिक आधार पर समीक्षा करेंगे और टैरिफ नीति द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के लिए सिफारिश करेंगे।

4. आरपीसीटीपी हर तिमाही अर्थात् 15 जुलाई; 15 अक्टूबर; 15 जनवरी और 15 अप्रैल के अंत में पारेषण प्रणालियों की अपनी समीक्षा और प्रणाली के विस्तार/सुदृढ़ीकरण के लिए अपनी सिफारिश राष्ट्रीय पारेषण समिति (एनसीटी) को अग्रेषित करेंगे। एनसीटी प्रस्तावों की जांच करेगी और उन्हें उनकी सिफारिशों के साथ सरकार को अग्रेषित करेगी।

5 . इसे माननीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्तरक्षित/-

(बिहारी लाल)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफैक्स: 23325242

ईमेल: transdesk-mop@nic.in

सेवा में,

1. पांच आरपीसीटीपी के सभी सदस्य।
2. सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार।
3. अध्यक्ष, सीईए, नई दिल्ली।
4. विद्युत मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत सभी सीपीएसयू के सीएमडी।
5. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सभी स्वायत्त निकायों के प्रमुख।
6. वित्त/बजट अनुभाग, विद्युत मंत्रालय।
7. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विद्युत/ऊर्जा सचिव।
8. सभी राज्य पारेषण यूटीलिटियों (एसटीयू) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

प्रति प्रेषित:

(i) माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव/ सचिव (विद्युत) के प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार/अपर सचिव (पारेषण)/सभी संयुक्त सचिव /आर्थिक सलाहकार/ निदेशक / उप सचिव, विद्युत मंत्रालय।

(ii) तकनीकी निदेशक, एनआईसी, विद्युत मंत्रालय, इस आदेश को विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए।

अनुलग्नक-2

स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति के लिए रूपरेखा

i. स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति पारेषण सेवा करार (टीएसए) की प्रभावी तिथि से 90 (नब्बे) दिनों के बाद नहीं की जाएगी और एससीओडी या वास्तविक सीओडी, जैसा भी मामला हो, के 30 (तीस) दिनों के बाद समाप्त होने वाली अवधि के लिए होगी।

ii. स्वतंत्र इंजीनियर के चयन की प्रक्रिया एकल चरण दो लिफाफा बोली प्रक्रिया पर की जाएगी।

iii. स्वतंत्र इंजीनियर के चयन के लिए अर्हता की आवश्यकता मुख्य रूप से परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में अनुभव या गुणवत्ता निगरानी सहित पारेषण परियोजनाओं (पारेषण लाइन और / या सब-स्टेशन) के निर्माण में स्वतंत्र इंजीनियर / ऋणदाता के इंजीनियर के रूप में अनुभव पर आधारित होगी।

iv. वित्तीय बोलियां स्वतंत्र अभियंता द्वारा मासिक आधार पर लिए जाने वाले शुल्क के रूप में होंगी।

v. चयन गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) मानदंड पर आधारित होगा।

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 10th August, 2021

Guidelines for Encouraging Competition in Development of Transmission Projects

No. 15/1/2017-Trans.—The Electricity Act, 2003 envisages competition in transmission and has provisions for grant of transmission licenses by the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) as well as State Electricity Regulatory Commissions (SERCs).

2. The National Electricity Policy notified on 12th February, 2005 interalia states that–

"5.3.1 The Transmission System requires adequate and timely investments and also efficient and coordinated action to develop a robust and integrated power system for the country.

5.3.2 Keeping in view the massive increase planned in generation and also for development of power market, there is need for adequately augmenting transmission capacity.

5.3.10 Special mechanisms would be created to encourage private investment in transmission sector so that sufficient investments are made for achieving the objective of demand to be fully met by 2012.

5.8.1 Considering the magnitude of the expansion of the sector required, a sizeable part of the investments will also need to be brought in from the private sector. The Act creates a conducive environment for investments in all segments of the industry, both for public sector and private sector, by removing barrier to entry in different segments. Section 63 of the Act provides for participation of suppliers on competitive basis in different segments which will further encourage private sector investment."

3. The Tariff Policy notified on 28th January, 2016 interalia states that –

"5.3 The tariff of all new generation and transmission projects of company owned or controlled by the Central Government shall continue to be determined on the basis of competitive bidding as per the Tariff Policy notified on 6thJanuary, 2006 unless otherwise specified by the Central Government on case to case basis.

Further, intra-state transmission projects shall be developed by State Government through competitive bidding process for projects costing above a threshold limit which shall be decided by the SERCs."

4. In order to facilitate the smooth and rapid development of transmission capacity in the country as envisaged in the National Electricity Policy, inter State /intra State transmission projects, other than those exempted by the Central Government, shall be implemented through tariff based competitive bidding.

5. These guidelines will be reviewed from time to time with the ultimate aim of developing all transmission projects in an efficient and economical manner.

PERSPECTIVE, SHORT TERM AND NETWORK PLANS

6. Central Transmission Utility (CTU) has to discharge all functions of planning and coordination relating to inter State transmission system according to section 38(2) (b) of the Electricity Act 2003. According to section 38(2) (c) of the Act, the CTU has to ensure the development of an e-fficient, coordinated and economical system of inter State transmission lines for smooth flow of electricity from generating stations to load centers.

7. According to Section 73(a) of the Act, the Central Electricity Authority (CEA) has to "advise the Central Government on the matters relating to the National Electricity Policy, formulate short-term and perspective plans for development of the electricity system and co-ordinate the activities of the planning agencies for the optimal utilization of resources to subserve the interests of the national economy and to provide reliable and affordable electricity for all consumers."

8. According to Section 3 subsection 4 of the Electricity Act, the CEA has to prepare the National Electricity Plan in accordance with the National Electricity Policy.

9. Para 3.2 of the National Electricity Policy provides "the CEA shall prepare short term and perspective plan".

10. According to the National Electricity Policy "the Central Transmission Utility (CTU) and State Transmission Utility (STU) have the key responsibility of network planning and development based on the National Electricity Plan in coordination with all concerned agencies as provided in the Act." Section 38(2) of the Electricity Act, inter alia, provides the following:

"The functions of the Central Transmission Utility shall be –

a. To undertake transmission of electricity through inter-State transmission system;

b. To discharge all functions of planning and co-ordination relating to inter-State transmission system with –

(i) State Transmission Utilities;

(ii) Central Government;

(iii) State Governments;

(iv) Generating companies;

(v) Regional Power Committees;

(vi) Authority;

(vii) Licensees;

(viii) Any other person notified by the Central Government in this behalf"

The Network Plan will be prepared as per the above provisions of the Electricity Act and the National Electricity Policy.

11. In view of the above the following plans will be prepared:

- Perspective Plan for fifteen years period will be prepared by CEA.
- Short Term Plan for five years period will be prepared by CEA.

  Both these plans form part of the National Electricity Plan.
- Network Plan will be prepared by the CTU based upon the National Electricity Plan.

  The Network Plan, Short Term Plan and the Perspective Plan will be hosted on the websites of the respective organizations, entrusted with the task of formulation of these plans.

12. The Network plan will be reviewed and updated as and when required but not later than once a year. The Network Plan would include the projects for new lines and substations, strengthening and up gradation of the existing lines and interregional transmission lines. The Network Plan will clearly identify the scope of the project, broad parameters such as design specifications including Voltage level, line configuration i.e S/C or D/C, functional specifications of conductor etc., length of transmission line and probable location of substation or converter station of HVDC transmission lines.

COMMITTEES ON TRANSMISSION

13. A National Committee on Transmission has been constituted by Ministry of Power, Government of India vide office order no 15/3/2017-Trans dated 4th November, 2019 and subsequent amendment no. 15/3/2018-Trans-Pt(5) dated 20th May 2021. The composition of the Committee is as follows:

1.	Chairperson, Central Electricity Authority (CEA)	Chairman
2.	Member (Power System), CEA	Member
3.	Member (Economic & Commercial), CEA	Member
4.	Joint Secretary level officer looking after transmission in M/o New & Renewable Energy, Govt. of India[@]	Member
5.	CMD, POSOCO	Member
6.	Director (Trans), M/o Power, Govt. of India	Member
7.	Chief Operating Officer, Central Transmission Utility (POWERGRID)	Member
8.	Advisor, NITI Aayog[#]	Member
9.	Two Experts from Power Sector *	Members
10.	Chief Engineer (from Power System Wing), CEA[#]	Member Secretary

[@] To be nominated by Secretary (MNRE)

[#] To be nominated by NITI Aayog/ CEA

* To be nominated by the Ministry of Power, Govt. of India from time to time, for a maximum period of two years from the date of their nomination.

14. Further, five (5) number of Regional Power Committee (Transmission Planning) have also been constituted by the Ministry of Power, Government of India vide office order no 15/3/2017-Trans dated 4th November, 2019.

The order containing therein the composition & Terms of Reference (ToR) of the committees is enclosed at **Annex-1**. The composition & Terms of Reference of the committees shall be as notified by Ministry of Power, Govt. of India from time to time.

PROJECT FORMULATION

15. Once the Perspective plan, the Short Term Plan and the Network Plan have been prepared; projects other than those exempted by the Central Government, will be covered under this Scheme for competitive bidding. In order to attract private investment in the transmission sector, it is very important to be able to make available all the information to the stakeholders, regarding new projects and their technical and other specifications. These projects would then need to be formulated with adequate details to enable competitive bidding to take place. Project Profile (PP) for these projects shall be prepared by CTU in consultation with CEA. The Project Profile (PP) must contain relevant data regarding the line i.e. voltage level, line configuration i.e. S/C or D/C, functional specifications of conductor etc. and functional specifications of the substations or converter stations (in case of HVDC line). In addition, a survey report containing one suggested route with approximate route length, type of terrain, max. altitude, snow zones, Wind zones, forest / wildlife infringement, infringement of endangered species habitat, vicinity to civil and defence Airports, major river/sea crossings & coal/ mineral mine areas likely to be encountered and location of substations or converter stations shall be prepared for these projects. The task of preparing survey report shall be allocated by National Committee on Transmission (NCT) by maintaining a roster amongst agencies namely CTU & BPCs. After actual decision regarding the mode of execution of any transmission project, the relevant survey report shall be procured by the agency bidding out the transmission project from the agency nominated by NCT for survey upon reimbursement of the cost incurred.

16. BPC will incur the expenditure for the preparatory activities of the projects including survey report for the projects allocated to them. BPC will recover this amount from the agency that finally undertakes the implementation of the project.